

न्यायालय - राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 62-पांच/96 विरुद्ध आदेश दिनांक 29-8-96 पारित
द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 64/91-92/निगरानी.

- 1- केदार सिंह
- 2- केशवसिंह
- 3 महेश सिंह पुत्रगण ब्रदीप्रसाद
निवासी ग्राम विलगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना

विरुद्ध

..... आवेदकगण

- 1- गजाधर प्रसाद पुत्र रामचन्द्र
- 2- मातादीन पुत्र गजाधर प्रसाद
- 3- रमेश चन्द्र पुत्र गजाधर प्रसाद
निवासीगण ग्राम विलगांव चौधरी
परगना जौरा जिला मुरैना

..... अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री एस.के. वाजपेई, अनावेदक क्रमांक 2.

आदेश

(आज दिनांक 2-9 -2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे
आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग,
मुरैना के प्रकरण क्रमांक 64/91-92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-8-96 के
विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः
दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

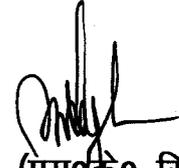




3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19-12-88 के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय में निगरानी 25.4.89 को प्रस्तुत की गई जिसे कलेक्टर ने अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 9-12-88 को उभयपक्ष की बहस श्रवण की गई और दिनांक 19-12-88 को आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश दिनांक 19-12-88 को ही उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा नोट किया गया । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने मुंशी की लापरवाही दर्शाने मात्र से निगरानी को समयावधि में न मानने का जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित है क्योंकि मुंशी जगदीश का कोई शपथपत्र भी प्रकरण में पेश नहीं किया । विलंब के संबंध में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम०के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर